

नहीं रहा और जहां तक संसद सदस्यों के सुझावों का सवाल है तो जब 2002 के अंत में और 2003 के प्रारंभ में जब यह लाइसेंस अवधि खत्म होगी और हम नया काम प्रारंभ करेंगे तो संसद सदस्यों के सुझावों को हम सम्मानित रूप से देखेंगे।

श्री एस०एस० अहलवालिया: सर, समय लगभग पूरा हो रहा है।

श्री सभापति: तो आप प्रश्न नहीं पूछना चाहते? चौधरी चुन्नी लाल।

चौधरी चुन्नी लाल: सर, मैं बहुत जल्दी से अपना सवाल पूछ लेता हूं। यह जो स्टॉल्स अलॉटमेंट की प्रक्रिया है, क्या माननीय मंत्री जी बताएंगे कि जिस तरह पेट्रोलियम विभाग में एल.पी.जी. और पेट्रोल पम्प का आवंटन आरक्षित अनुपात के अनुसार किया जाता है, क्या रेल मंत्रालय इस पर विचार कर रहा है कि इस तरह के अलॉटमेंट में अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए आरक्षण का ध्यान रखा जाएगा। और अगर रखा जाएगा तो क्या कार्यवाही होगी?

श्री दिग्विजय सिंह : माननीय सभापति जी, अभी तक जो तरीका हम अपनाते हैं, उन तरीकों का हम ने जिक्र किया है और जब 2002 के अंत में या 2003 के आपसास फिर से रिनुअल होने लगेगा, उस समय हम इस का भी ख्याल रखेंगे कि समाज के पिछड़े हुए लोगों के लिए कितना प्रावधान हम इन कामों के लिए कर सकते हैं। हम उस का ख्याल अवश्य रखेंगे।

डा.वाई.लक्ष्मी प्रसाद: सर, वर्ष 2002 के अंत में मौजूदा लाइसेंसिंग अवधि समाप्त होने वाली है तो क्या यह आश्वासन मंत्री जी दे सकते हैं कि ए.एच व्हीलर और अन्य जो संस्थाएं हैं, उन के बीच के डिस्क्रिमिनेशन को आप समाप्त करेंगे?

श्री दिग्विजय सिंह: निश्चित रूप से, जब हम ने कहा है कि उन की मोनोपोली को समाप्त करेंगे तो निश्चित रूप से खुले रूप से सब लोगों का जो हक और अधिकार है, वही व्हीलर का भी हक और अधिकार रहेगा।

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS

Extra Seats for Engineering Colleges in Andhra Pradesh

*181. SHRI YADLAPATI VENKATRAO: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government propose to open a new regional centre in Andhra Pradesh to inspect opening of new engineering colleges:

(b) if so, the details thereof; and

(c) how many extra seats are proposed to be given in Andhra Pradesh in the near future?

[1 December, 2000)

RAJYA SABHA

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRIMATI SUMITRA MAHAJAN):
(a) and (b) No, Sir.

(c) Granting of approval for increasing in seats is a continuous process based on various factors such as number of applications received, fulfilment of laid down norms and standards, availability of infrastructural facilities and assessment of manpower requirements in the country.

Welfare of Aged Persons

*186. SHRI RAMDAS AGARWAL: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to an editorial published in the Hindustan Times dated 11th November, 2000, on the occasion of International Day of the Older Persons, wherein it is stated "the fact is that 'National Policy on Older Persons' has been fossilised in some dusty official file";

(b) whether the Prime Minister himself has emphasized the need for such organisations;

(c) if so, what is the reaction of Government thereto; and

(d) what steps are being taken in this regard by the Ministry?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI A. RAJA): (a) to (d) The Ministry of Social Justice & Empowerment has taken various steps for implementation of the policy announced in January, 1999. The details of the steps taken are as follows:—

- (i) The National Council for Older Persons (NCOP) has been set up in May, 1999, to operationalise the National Policy for Older Persons (NPOP). The Council met on 13th June, 2000, to discuss the draft action plan for implementation of the National Policy on Older Persons.
- (ii) AADHAR has been set up to function as Secretariat of National Council for Older Persons (NCOP). It is being administered by Agewell Foundation, an NGO, with the financial assistance from